FINANCIAL EXPRESS, Delhi, 23.8.2024
Page No. 10, Size:(2.18)cms X (16.22)cms.

India top oil buyer from Russia in July, pips China

NIDHI VERMA
New Delhi, August 22

INDIA OVERTOOK CHINA as the world's biggest importer of Russian oil in July as Chinese refiners bought less because of lower profit margins from producing fuels, a comparison of import data showed.

Russian crude made up a record 44% of India's overall imports last month, rising to a record 2.07 million barrels per day (bpd), 4.2% higher than in June and 12% more than a year ago, data on Indian shipments from trade and industry sources showed.

That surpassed China's July oil imports from Russia of 1.76 million bpd via pipelines and shipments, based on Chinese customs data.

Indian refiners have been gorging on Russian oil sold at discounts after Western nations imposed sanctions against Moscow and curtailed their energy purchases in response to Russia's invasion of Ukraine. "India's requirement for Russian oil is going to go up as long as there are no further tightening of sanctions," an Indian refining source said. India's trade with Russia has increased since Russia began its war against Ukraine in February 2022 mainly because of oil and fertiliser imports, a move helping to keep a lid on global prices and controlling inflation.

India's rising purchases are changing the flow of Russian ESPO Blend crude from traditional Chinese buyers to South Asia. ESPO imports to India jumped in July to 188,000 bpd as larger Suezmax vessels were used, according to the data. —REUTERS

FINANCIAL E

BUSINESS LINE, Delhi, 23.8.2024
Page No. 2, Size:(9.88)cms X (7.57)cms.

'No proposal for MRPL-HPCL merger'

Our Bureau
Mangaluru

Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL) has said there is no proposal for the merger of MRPL with HPCL.

Replying to queries at the company's 36th annual general meeting (virtual) on Thursday, M Shyamprasad Kamath, its Managing Director, said MRPL, being a subsidiary of ONGC, will be directed by the decisions and the directions coming from its parent.

OTHER QUERIES

Talking about the company's investment roadmap, he said MRPL is devising strategic initiatives with a dual focus on risk management and wealth creation. Stating that the company is exporting around 34 per cent of its products, he said, "We are aiming to reduce this by establishing a strong presence in the retail market."

To achieve this, the company is aiming to sell 1 million tonnes of products in its retail outlets in the next three-five years.

On the impact of geopolitical tensions in West Asia, Kamath said MRPL has been focusing on reducing its dependence on West Asia for crude oil supplies.

It has been reduced to around 35 per cent in the last three years, he said.

The company's refinery processes at least three-five new crude oil grades every year.

Expansion of crude oil sources ensures that it is ready to source crude from other sources in any situation, he added.

Kamath said MRPL is trying to meet its net zero targets by 2038.

ECONOMIC TIMES, Delhi, 23.8.2024
Page No. 5, Size:(10.46)cms X (10.74)cms.

PNGRB Seeks Common Carrier Status for PSUs' ATF Pipelines

Sanjeev Choudhary

New Delhi: The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (PNGRB) is seeking to declare state oil companies' jet fuel (ATF) pipelines to some of the biggest airports in the country as common carriers in a bid to give private players equitable access and turn the jet fuel market more competitive.

PNGRB has sought to declare Indian Oil's ATF pipelines to Delhi, Kolkata, Chennai and Lucknow airports and Bharat Petroleum's pipeline to Kochi airport as common or contract carriers. These pipelines mostly connect airports with refineries and are far more economical to use than alternative road transport.

A common carrier status will permit the use of these pipelines by private sector players such as Reliance Industries, bringing down their transport costs and making them more competitive in the ATF market.

Most major airports have open access fuel farm infrastructure or fuel supply mechanisms through browsers operated by various oil companies. However, access to pipelines is crucial to keep ATF suppliers competitive.

"Without a common carrier or contract carrier pipeline, it becomes challenging to fully realise the benefits of an open fuel market because new and smaller fuel marketers cannot easily access the existing infrastructure," the PNGRB said, defending its move. The regulator is seeking wider consultation on the subject.

EQUITABLE ACCESS

A common carrier status will permit the use of these pipelines by pvt sector players such as RIL, bringing down their transport costs and making them more competitive in the ATF market

"It is crucial that the existing pipelines, which have historically been controlled by a limited number of oil marketing companies, be designated as common carriers or contract carriers," it said. "This designation would ensure that all marketers have equal opportunity to utilise these pipelines, fostering a more competitive and fair market environment."

This would potentially lower prices and improve "service quality for end consumers, including airlines and, indirectly, passengers," the regulator said.

DAINIK JAGRAN (JAGRAN CITY), Delhi, 23.8.2024
Page No. 2, Size:(13.77)cms X (7.83)cms.

दरवाजे पर लगाया पीएनजी मीटर, अंदर जला रहे कोयला

हसीन शाह ● जागरण

साहिबाबाद: प्रदेश और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों की कार्रवाई से बचने के लिए उद्यमी और रेस्टोरेंट संचालक इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आइजीएल) से पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) का मीटर लगवाने के बाद कनेक्शन नहीं जुड़वा रहे हैं। गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, हापुड़ और दिल्ली में ऐसे लोगों की संख्या 938 है। दरवाजे पर मीटर लगवा फैक्ट्री और रेस्टोरेंटों के अंदर कोयला जला रहे हैं। इससे प्रदूषण की मात्रा बढ़ रही है। सबकुछ जानते हुए आइजीएल के अधिकारियों ने भी चुप्पी साध रखी है।

ग्रेप लागू होने पर पीएनजी वाली फैक्ट्रियां ही संचालित होती हैं। कोयले सहित अन्य प्रदूषणकारी ईंधन से चलने वाली फैक्ट्रियों को बंद करा दिया जाता है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम लगातार इसकी निगरानी करती है। वहीं रेस्टोरेंटों के तंदूर में भी कोयला जलाने पर रोक लग जाती है। कुछ उद्यमियों ने अधिकारियों की कार्रवाई से बचने के लिए आइजीएल से पीएनजी लगवाने के लिए आवेदन कर मीटर लगवा लिया है। मीटर लगवाने के बाद मुख्य लाइन से कनेक्शन जुड़वाने की जिम्मेदारी उद्यमी की होती है। उद्यमी ही उसमें पैसे खर्च करता है। अधिकारियों की कार्रवाई से बचने के लिए गेट के बाहर केवल मीटर लगवाकर छोड़ दिए हैं। उत्तर प्रदेश और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी आते हैं और मीटर देखकर चले जाते हैं। वह चेकिंग के लिए अंदर तक नहीं जाते हैं। इसकी जानकारी आइजीएल के अधिकारियों को भी है, लेकिन वह इस संबंध में संबंधित विभागों को अवगत नहीं करा रहे हैं। आइजीएल के मीडिया प्रभारी ने बताया कि उनकी जानकारी में आया है कि गाजियाबाद में 60, गौतमबुद्ध नगर में 191, हापुड़ में पांच और दिल्ली 682 लोगों ने मीटर लगवाने के बाद कनेक्शन नहीं जुड़वाया है। इस संबंध में वह जल्द ही संबंधित विभागों के अधिकारियों को अवगत कराएंगे। जिससे उन पर कार्रवाई हो सके।

कार्रवाई से बचने के लिए फैक्ट्री के बाहर लगा पीएनजी मीटर ● सौ. आइजीएल

गाजियाबाद में इकाइयां

2,700
कुल औद्योगिक इकाइयां

5,200
के करीब हैं छोटी औद्योगिक इकाइयां

21,000
से अधिक सूक्ष्म औद्योगिक इकाइयां

स्थान	बिना पीएनजी के लगे मीटर
गाजियाबाद	60
गौतमबुद्ध नगर	191
हापुड़	5
दिल्ली	682

हम पीएनजी मीटर लगी फैक्ट्रियों में भी प्रयोग होने वाले ईंधन की जांच करेंगे। अभी मीटर लगने वाली पीएनजी फैक्ट्रियों पर कार्रवाई नहीं हुई है। -विकास मिश्र, क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

अधिकारी हो रहे गुमराह

कुछ उद्यमियों ने पांच वर्ष पहले पीएनजी के मीटर लगवाए थे, लेकिन कनेक्शन अभी तक नहीं जुड़वाया। सवाल है ये है कि अधिकारी आखिर बाहर से बाहर मीटर देखकर ही क्यों चले जाते हैं? वह चेक क्यों नहीं करते हैं कि मीटर चालू है या नहीं? फैक्ट्री के अंदर पीएनजी का प्रयोग हो रहा है या कोयले का ? सूत्रों की माने तो अधिकारी जानबूझकर इन सब बातों को जानने की कोशिश नहीं करते हैं। इस लापरवाही का सीधा असर पर्यावरण पर पड़ रहा है। यही वजह है कि सर्दियों में प्रदूषण का स्तर रेड जोन में चला जाता है। लोगों को सांस लेना भी भारी हो जाता है।

DAINIK JAGRAN (JAGRAN CITY), Delhi, 23.8.2024
Page No. 1, Size:(2.58)cms X (7.77)cms.

नाहरपुर में शुरू हुई पीएनजी गैस की आपूर्ति

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली: रोहिणी विधानसभा के अंतर्गत वार्ड 52-एफ के नाहरपुर गांव में पीएनजी गैस की आपूर्ति शुरू हो गई है। सांसद योगेंद्र चांदोलिया व विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने गैस आपूर्ति का लोकार्पण किया। इस सुविधा से फिलहाल से दो से ढाई हजार परिवार लाभान्वित होंगे। इस अवसर पर सांसद योगेंद्र चांदोलिया ने कहा कि नाहरपुर गांव के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। रोहिणी से विधायक विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि गांव में बहुत जल्द ही वाल्मीकि चौपाल का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। कार्यक्रम में वार्ड 52-एफ से निगम पार्षद ऋतु गोयल, पूर्व विधायक जय भगवान अग्रवाल, पूर्व उपमहापौर नीलम गोयल, नाहरपुर आरडब्ल्यूए के प्रधान नरेश राव, रोहिणी फेडरेशन के अध्यक्ष आर्य मुनि, एसएल सागर, ओपी मल्होत्रा, मास्टर रामकिशन यादव, सतबीर सैनी, सुखबीर सैनी आदि उपस्थित रहे।

RASHTRIYA SAHARA, Delhi, 23.8.2024
Page No. 5, Size:(17.89)cms X (24.70)cms.

भलस्वां लैंडफिल साइट पर 30 लाख टन कचरे का होगा निस्तारण

नई दिल्ली (एसएनबी)। मेयर डॉ शैली ओबरॉय ने कहा कि दिल्ली नगर निगम की 'आप' सरकार शहर में स्थित कूड़े के पहाड़ों को हटाने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में सदन की बैठक में भलस्वा लैंडफिल साइट पर लेगेसी कचरे के निस्तारण के दूसरे चरण में 30 लाख टन कचरे के निस्तारण को मंजूरी प्रदान की गई है। मेयर ने बताया कि सुलतानपुर डबास गांव में एक और सैनिटरी लैंडफिल साइट स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की गई है।

■ आईजीएल के सहयोग से सीबीजी संयंत्र किया जाएगा स्थापित

मेयर डॉ शैली ओबरॉय ने कहा कि एमसीडी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करेगा। इसके अंतर्गत आईजीएल निगम के अधिकार क्षेत्र में कंप्रेस्ड बायो गैस संयंत्र स्थापित करेगा। इसके साथ ही एकीकृत सीबीजी-सीएनजी फ्यूल स्टेशन भी स्थापित करेगा। गाजीपुर स्थित बूचड़खाने पर वेस्ट को सुखाने का संयंत्र स्थापित करेगा। इस संयंत्र को स्थापित करने से जानवरों के अपशिष्ट को लैंडफिल साइट पर जाने से रोकने में मदद मिलेगी।

मेयर ने कहा कि मध्य क्षेत्र के लाजपत नगर भाग-4 स्थित अमर कॉलोनी के कम्युनिटी हॉल के प्रथम तल के एक कमरे में डाकखाना संचालित करने की भी मंजूरी प्रदान की गई है। सिविक सेंटर के ई-4, ब्लॉक के भूतल पर एसबीआई एटीएम/ई लॉबी स्थापित करने के लिए लीज पर स्थान देने संबंधी मंजूरी प्रदान की गई है। रेलवे के इंद्रपुरी हाल्ट स्टेशन पर फुटओवर ब्रिज बनाने के लिए अतिरिक्त भूमि आवंटित करने संबंधी प्रस्ताव को भी सदन से पारित करा दिया गया है। डॉ शैली ओबरॉय ने कहा कि निगम के पार्कों के रखरखाव के लिए उद्यान विभाग द्वारा अतिरिक्त कर्मियों को लगाने संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की गई है।

DAINIK BHASKAR, Delhi, 23.8.2024
Page No. 1, Size:(20.13)cms X (13.00)cms.

एमसीडी • आईजीएल से समझौते के तहत कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र स्थापित होगा

सुल्तानपुर डबास में सेनेटरी लैंड फिल साइट बनेगी, भलस्वा से 30 लाख टन कचरे का निस्तारण होगा

भास्कर न्यूज | नई दिल्ली

दिल्ली में कूड़े की 3 लैंड फिल साइटों के भर जाने के बाद अब एमसीडी ने नई लैंड फिल साइट की तलाश शुरू कर दी है। नगर निगम ने सुल्तानपुर डबास गांव में सेनेटरी लैंड फिल साइट बनाने का प्रस्ताव पास कर दिया है। इस प्रस्ताव के बाद एमसीडी सुल्तानपुर डबास गांव में लैंड फिल साइट बनाएगी। नई लैंड फिल साइट बनने के साथ ही दिल्ली में 4 लैंड फिल साइट हो जाएंगी। महापौर शैली ओबेरॉय ने बताया कि सुल्तानपुर डबास गांव में लैंड फिल साइट बनाने के प्रस्ताव को सदन से मंजूरी दे दी गई है। जल्द ही इस पर काम शुरू किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ भलस्वा लैंड फिल साइट को खाली करने के लिए यहां से निकलने वाले लेगेसी कचरे (ठोस कचरे) के निस्तारण के लिए भी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। प्रस्ताव के अनुसार भलस्वा लैंड फिल साइट से 30 लाख टन लेगेसी कचरे का निस्तारण किया जाएगा। साथ ही एमसीडी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करेगा, जिसके तहत आईजीएल निगम के अधिकार क्षेत्र में कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र स्थापित करेगा। इसके साथ ही एकीकृत सीबीजी-सीएनजी फ्यूल स्टेशन भी स्थापित करेगा।

गाजीपुर : गोबर सुखाने के लिए लगेगा संयंत्र

गाजीपुर बूचड़खाने पर इंजेस्ता, 5 वेस्ट और गोबर सुखाने का संयंत्र स्थापित किया जाएगा। मेयर ने बताया कि इस संयंत्र को स्थापित करने से जानवरों के अपशिष्ट को लैंड फिल साइट पर जाने से रोकने में मदद मिलेगी।

एमसीडी के लिए आसान नहीं नई लैंड फिल साइट बनाना

एमसीडी के लिए नई लैंड फिल साइट बनाना आसान नहीं है। सुल्तानपुर डबास में ही लैंड फिल साइट का बीते दिनों विरोध हुआ था। सोनिया विहार, घोंडा गुजरान और रानी खेड़ा में विरोध के बाद फैसले को पलटना पड़ा था।